Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

मार्च (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- प्रधानमंत्री ने झारखंड में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया 3
- मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने केज फार्मिंग की समीक्षा के लिये गेतलसूद बांध का दौरा किया 3
- PESA के सुदृढ़ीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 4
- नितिन गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी 6
- झारखंड को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिली 6
- झारखंड ने उच्च शिक्षा के लिये योजनाएँ शुरू कीं 7
- झारखंड ने छात्रों के लिये मुफ्त बैग की घोषणा की 7
- झारखंड के मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेजों की नींव रखी 8
- केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय संस्कृति केंद्र का शिलान्यास किया 9

नोट :

झारखंड

प्रधानमंत्री ने झारखंड में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद ज़िले के सिंदरी में उर्वरक, रेल, विद्युत और कोयला क्षेत्रों पर केंद्रित कई विकास पहलों की शुरुआत की, जिनकी कुल लागत 35,700 करोड़ रुपए है।
  - 8900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) सिंदरी उर्वरक संयंत्र का लक्ष्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे देश भर के किसानों को लाभ होगा।
    - गोरखपुर और रामागुंडम में इसी तरह के प्रयासों के बाद यह भारत में पुनसंचालित होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है।
  - चतरा में करीब 7500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (STPP) की यूनिट 1 का भी उद्घाटन किया जा रहा है।
    - इस परियोजना से राज्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ने, रोज़गार उत्पन्न होने और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें रेलवे लाइनों का विस्तार और सोन नगर-अंडाल लाइन तथा मोहनपुर-हंसडीहा लाइन जैसे नए मार्ग शामिल हैं।
  - इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  - कार्यक्रम के दौरान तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जानी है, जिनमें देवघर-डिब्रूगढ़ ट्रेन सेवा, टाटानगर और बादामपहाड़ के बीच मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन सेवा (दैनिक) एवं शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी शामिल है।

मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने केज फार्मिंग की समीक्षा के लिये गेतलसूद बांध का दौरा किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मत्स्य विभाग के सचिव ने केज फार्मिंग की प्रगति की समीक्षा के लिये राँची के गेतलसूद बांध का दौरा किया। यह समीक्षा झारखंड मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से की गई।

मुख्य बिंदु:

- गेतलसूद जलाशय केज फार्मिंग के माध्यम से पंगेसियस और तिलापिया मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- केज फार्मिंग पर कार्य वर्ष 2012-13 में शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत 365 पिंजरे की स्थापना के साथ महत्त्वपूर्ण सफलता मिली।
  - इन पिंजरों ने 25 लाख से अधिक फिंगरलिंग (एक छोटी मछली) के वार्षिक भंडारण के साथ, मछली की आबादी में वृद्धि में योगदान दिया है।
  - बाज़ार तक पहुँच पहले से ही स्थापित है, स्थानीय रूप से उत्पादित मछली आस-पास के बाज़ारों में औसतन 120 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेची जाती है, जो क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान करती है।

नोट :

- नीली क्रांति से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र योजना (CSS) के तहत, मत्स्य विभाग ने वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक मत्स्य पालन के लिये एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना शुरू की।
  - इस योजना के तहत कुल 14,022 पिंजरे स्वीकृत किये गए, जिसकी परियोजना लागत 420 करोड़ रुपए है।
  - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत, 44,908 पिंजरों के लिये मंज़ूरी दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लागत 1292.53 करोड़ रुपए है।

केज फार्मिंग

- इसमें जाल के पिंजरे में बंद रहते हुए मौजूदा जल संसाधनों में मछलियों को बढ़ाना शामिल है जो जल के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है।
- यह एक जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली है जो बड़ी संख्या में मछलियों को रखने और पालने के लिये एक गोल या चौकोर आकार के फ्लोटिंग जाल के साथ एक फ्लोटिंग फ्रेम, जाल सामग्री एवं रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ मूरिंग सिस्टम से बनी होती है तथा इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है।
- पिंजरे के फार्म प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लिये इस तरह से स्थित हैं, जो मछली को ऑक्सीजन और अन्य उपयुक्त प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

भारत में नीली क्रांति

- इसे भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना (FYP) के दौरान लॉन्च किया गया था जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक चली थी, जिसके दौरान सरकार ने मत्स्य किसान विकास एजेंसी (FFDA) को प्रायोजित किया था।
- 8वीं FYP के दौरान, वर्ष 1992-97 तक, गहन समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया गया था।
- समय के साथ, तूतीकोरिन, पोरबंदर, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में मत्स्यन के बंदरगाह स्थापित किये गए।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMSSY)

- PMMSY को 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है।
- संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

PESA के सुदृढ़ीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 को मज़बूत करने पर दूसरा दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन राँची में आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने समापन सत्र को संबोधित किया और पीएम-जन मन योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
- PESA के कार्यान्वयन को मज़बूत बनाने और PESA क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका पर चर्चा क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन दिवस की मुख्य विशेषताएँ थीं, ताकि प्रतिभागियों के बीच ज्ञान साझा करने में सहायता की जा सके, PESA के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया जा सके।
- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे सामान्यत: PESA अधिनियम के नाम से जाना जाता है, के प्रावधानों को मज़बूत करने और प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपन्न हुआ।

नोट :

- क्षेत्रीय सम्मेलन ने PESA के सफल और लक्षित कार्यान्वयन की दिशा में महत्त्वपूर्ण गति प्राप्त की तथा सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी एवं व्यावहारिक योगदान के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया, जिससे अधिनियम कार्यान्वयन में आगे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- भाग लेने वाले पाँच राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के प्रतिभागियों ने अपने सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करते हुए, उत्साह तथा आशा से भरे समापन सत्र को छोड़ दिया।
- राँची में क्षेत्रीय सम्मेलन PESA के सफल, परिकल्पित और प्रभावी कार्यान्वयन की गति को बनाए रखने के एक शानदार संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996

- ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन पारित किया गया था।
- इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।
- हालाँकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था।
- वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिये पेसा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया।
- PESA ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान कीं, जबकि राज्य विधानमंडल ने पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये एक सलाहकार की भूमिका दी है।
  - ग्राम सभा को सौंपी गई शक्ति को उच्च स्तर से कम नहीं किया जा सकता है और हर जगह स्वतंत्रता होगी।
- PESA को भारत में जनजातीय कानून की रीढ़ माना जाता है।
- PESA निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन के लिये खड़ा है।
- ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य प्रदान किये गए हैं:
  - विस्थापित व्यक्तियों के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।
  - जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आस्था, संस्कृति का संरक्षण
  - लघु वनोत्पाद का स्वामित्व
  - स्थानीय विवादों का समाधान
  - भूमि हस्तांतरण की रोकथाम
  - ग्रामीण बाज़ारों का प्रबंधन
  - नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना
  - साहूकारी पर नियंत्रण का अभ्यास
  - अनुसूचित जनजातियों से जुड़े कोई अन्य अधिकार

पीएम-जनमन योजना

- पीएम-जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।
- यह योजना (केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं PVTG समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।
- यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले 11 महत्त्वपूर्ण कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो PVTG वाले गाँवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
  - इसमें पीएम-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

नोट :

- इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिये वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली तथा सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शामिल है।
- इस योजना से PVTG के साथ भेदभाव एवं उनके बहिष्कार के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय व मूल्यवान योगदान को मान्यता और महत्त्व देकर PVTG के जीवन की गुणवत्ता तथा कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है।

नितिन गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- इन परियोजनाओं में तुपुदाना से कुंडी बारटोली खंड (खूंटी बाईपास सहित) के चार लेन का निर्माण तथा बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है।
- इन परियोजनाओं से समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें आसान व सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेंगी।
- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोज़गार एवं उद्यमिता के नये अवसर सृजित होंगे।

झारखंड को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पीएम ने तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, जो झारखंड की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच संचालित होगी।

मुख्य बिंदु:

- देश भर में कई अन्य रेलवे परियोजनाओं के अनावरण के साथ-साथ पीएम ने अहमदाबाद से सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
- राज्यपाल के अनुसार रांची स्टेशन के सौंदर्यीकरण और विभिन्न सुविधाओं की स्थापना के लिये राज्य में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ चल रही हैं।
  - राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची-पटना रूट पर शुरू हुई, जिसे 27 जून, 2023 को हरी झंडी दिखाई गई।
  - रांची और हावड़ा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को 24 सितंबर 2023 को शुरू किया गया।
- पीएम ने रांची-बोंडामुंडा रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया और रांची, हटिया, गोविंदपुर रोड, इटकी, मुरी, पिस्का, सिल्ली, टांगरबासुली, तातीसिलवाई स्टेशनों, बरकाकाना, रांची रोड एवं प्रधानखंता स्टेशनों पर 'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना के तहत स्टॉलों का भी उद्घाटन किया।

'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना

- यह रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेलवे की एक पहल है।
- इसे 25 मार्च, 2022 को 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया था।
- यह स्थानीय लोगों को देश भर में स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिये विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किये गए बिक्री आउटलेट प्रदान करता है।
- यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद द्वारा डिज़ाइन की गई है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक प्रचार केंद्र के रूप में बनाना और स्थानीय एवं स्वदेशी विनिर्माण उत्पादों का प्रदर्शन करना है।

नोट :

वंदे भारत ट्रेन

- यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड, स्व-चालित ट्रेन है जिसे राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद से गति एवं यात्री सुविधा के मामले में भारतीय रेलवे के लिये अगली बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
- पहली वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ((ICF), चेन्नई द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था।
- वंदे भारत अलग-अलग इंजनों द्वारा खींचे जाने वाले यात्री डिब्बों की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक को अपनाने का भारत का पहला प्रयास था।
- ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन, हालाँकि जटिल है, तेज़ है, रखरखाव में आसान है, कम ऊर्जा की खपत करता है और ट्रेन संचालन में अधिक लचीला है।

झारखंड ने उच्च शिक्षा के लिये योजनाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों ?

राँची के ताना भगत स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से दो योजनाएँ पेश कीं।

- दो योजनाएँ हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति।

मुख्य बिंदु:

- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, छात्र 4% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपए तक का संपार्श्विक-मुक्त शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  - ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद शुरू होता है, जिसमें सरकार गारंटर के रूप में कार्य करती है।
- मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 15,000 रुपए प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
- उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी उल्लेख किया, जो छात्रों को 2,500 रुपए का मासिक स्टाइपेन्ड प्रदान करने वाली योजना है।
  - इस स्टाइपेन्ड का उद्देश्य कोचिंग के दौरान रहने वाले खर्चों को कम करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएँ शैक्षिक गतिविधियों में बाधा न डालें।
- मुख्यमंत्री ने राँची में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में एक नवनिर्मित 3D थियेटर का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना

- यह योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे- JEE, NEET, CLAT, NHMCET, NIFT-CET आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है।
- छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये 2500/- रुपए की मासिक सहायता राशि भी प्राप्त होगी।
- छात्रों का चयन उनके 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा और कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।

झारखंड ने छात्रों के लिये मुफ्त बैग की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में कक्षा I से VIII में नामांकित लगभग 37 लाख छात्रों को स्कूल बैग के अलावा प्रत्येक वर्ष स्कूल किट के हिस्से के रूप में किताबें और अन्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की गई।
- कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 53 प्रस्ताव लिये गए, जिनमें से अधिकांश में सड़क परियोजनाएँ, सिंचाई और जल आपूर्ति कार्य, ग्रामीण विकास कार्य शामिल थे।
  - सरकार प्रत्येक तीन महीने में प्रति आँगनवाड़ी गैस सिलेंडर की एक बार रिफिलिंग प्रदान करेगी।
  - झारखंड कदन्न मिशन की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई।
    - सरकार का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में कदन्न कृषि का क्षेत्र मौजूदा 40,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5,00,000 हेक्टेयर करना है।
  - किसान समृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना है।

नोट:

झारखंड सरकार कदन्न विशेष रूप से रागी (फिंगर मिलेट/कदन्न) को बढ़ावा दे रही है जो राज्य में बहुत बिखरे हुए तरीके से उगाया जाता है। उच्च पोषक मूल्य के कारण राज्य सरकार राज्य आजीविका नीति के तहत कदन्न को बढ़ावा दे रही है जो पंचायत विभाग के अधीन है और ज़्यादातर स्कूली बच्चों एवं अस्पतालों के लिये दोपहर के भोजन में परोसा जाता है।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेजों की नींव रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत पश्चिमी सिंहभूम में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये चाईबासा के हाटगम्हरिया और बंदगाँव में एक-एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने 2 अरब, 31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 135 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1 अरब 7 करोड़ रुपए से अधिक की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- लाभार्थियों के बीच एक अरब 72 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का वितरण किया गया।
- कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत डिग्री कॉलेजों की शुरुआत से क्षेत्र के शैक्षिक परिदृश्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
  - यह पहल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और अपने युवाओं के लिये सुलभ शैक्षिक अवसरों को सुविधाजनक बनाने के राज्य के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।
  - कुड़ुख, हो, मुंडारी और संथाली जैसी जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों से शुरू की जा रही है।
- मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये सरकार की ओर से कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
  - आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिये छात्रवृत्ति राशि तीन गुना बढ़ा दी गई है।
  - छात्राओं को सावित्रीबाई किशोरी सावित्री योजना से जोड़ा जा रहा है।
  - गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करने के लिये 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है।
  - मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है।
  - राज्य सरकार आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिये शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति दे रही है।

नोट :

सवित्रीबाई किशोरी सवित्री योजना

- इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा, बाल विवाह को समाप्त करना और महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देना है।
- इस योजना के तहत किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
- इसके तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिये 40 हज़ार रुपए की सहायता दे रही है।
  - कक्षा 8 में छात्राओं को 2500 रुपए, कक्षा 9 में 2500 रुपए, कक्षा 10 में 5000 रुपए, कक्षा 11वीं और 12वीं में 5000-5000 रुपए तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपए दिये जाएंगे।
  - इस तरह किशोरियों को कुल 40 हज़ार रुपए दिये जायेंगे।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

- यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
- विद्यार्थियों को 4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
- लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।
- जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना

- यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी
- मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 15,000 रुपए प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय संस्कृति केंद्र का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री; कृषि एवं किसान कल्याण अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले में 'जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र' की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- यह संग्रहालय झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत को चित्रित करने और संरक्षित करने का एक प्रयास है, साथ ही समृद्ध आदिवासी जीवन शैली एवं संस्कृति को प्रदर्शित करता है।
  - केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करके इस पहल को स्वीकृति दे दी है।
  - इस केंद्र को भविष्य में एक जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जिसमें कारीगरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पर्यटन के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिये जगह मिलेगी।
  - यह क्षेत्र की भौतिक और अमूर्त जनजातीय संस्कृति, इसके इतिहास एवं विरासत का प्रदर्शन करेगा।
- एक अन्य कार्यक्रम में, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन (BAJSS) में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हाल ही में पुनर्निर्मित राष्ट्रीय अद्वितीय जनजातीय संग्रहालय, ई-लाइब्रेरी और एसटी गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया।
  - BAJSS की स्थापना वर्ष 1948 में अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर द्वारा की गई थी, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था, जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, जिन्होंने आदिवासी लोगों के उत्थान के लिये कार्य किया था।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :